प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
13.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

आर्थिक सर्वेक्षण

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की गैर मौजूदगी में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 प्रस्तुत किया। बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10 दशमलव 2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 2 लाख 32 हज़ार एक सौ 85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय विकास दर करीब 7 फीसदी के आस–पास है। वहीं प्रदेश में विकास दर के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 के मुकाबले वर्तमान वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 9 दशमलव 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के 2 लाख 34 हज़ार 7 सौ 82 रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2024–25 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख 57 हज़ार 2 सौ 12 रुपए तक पहुंच गई है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 22 हज़ार 4 सौ 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 45 दशमलव 3 फीसदी आंका गया है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान भी बढ़कर 9 दशमलव 24 फीसदी है, जबकि श्रम व इससे जुड़े हुए क्षेत्रों का योगदान 15 दशमलव 2 फीसदी आंका गया है। अर्थव्यवस्था के विकास में पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, परिवहन और हस्तशिल्प क्षेत्रों का योगदान 7 दशमलव 78 फीसदी है।

प्रश्नकाल

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि भू–अधिनियम की धारा 118 हिमाचल प्रदेश में निवेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जब तक धारा 118 में संशोधन कर इसके प्रावधानों को सरल नहीं किया जाता, तब तक प्रदेश में औद्योगिक विकास को सही अर्थों में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी और जीतराम कटवाल द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उद्योग मंत्री ने विपक्ष से धारा 118 के सरलीकरण के मुद्दे पर सरकार का साथ देने की अपील की ताकि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लंबी अवधि की नीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि समय–समय पर उद्योग बंद होना एक सामान्य प्रक्रिया है और सरकार किसी भी बंद हुए उद्योग को नहीं चला सकती। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग चलाने के लिए सिर्फ प्रोत्साहन देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योगपति उद्योग बंद होने पर इसकी सूचना सरकार को नहीं देता। उद्योग मंत्री ने कहा कि बीते दो सालों में सिंगल विंडो अथॉरिटी के माध्यम से एक सौ 43 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इनके माध्यम से 8 हज़ार 3 सौ 80 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इन उद्योगों में 17 हजार 7 सौ 30 लोगों को रोजगार मिलेगा।

वॉकआउट

इस बीच विपक्ष ने आज सदन में कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में जुलाई 2024 में हुए उपचुनाव में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान कई महिला मंडलों को 50–50 हजार रुपए हस्तांतरित करने के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे और सदन से बाहर चले जाने के बाद उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह पहले से तय था कि विपक्ष को सदन से बाहर जाना ही था, क्योंकि उनके पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने विपक्ष के इस रवैये को 'सदन की परंपराओं के खिलाफ' बताया और कहा कि अगर भाजपा के पास कोई ठोस प्रमाण हैं, तो वे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। इस संबंध में भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सवाल पूछा था, जिस पर सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर विपक्ष ने पहले सदन में हंगामा किया और फिर पूरा विपक्ष सदन से उठकर बाहर चला गया।

जयराम

वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन से वॉकआउट के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि देहरा विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसे बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर देहरा से भाजपा उम्मीदवार चुनाव आयोग या कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

.....